

घटना घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...



www.ghatatighatana.com

अम्बिकापुर,तर्ष 22, अंक - 272- रविवार 02- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये

RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीवन. कं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

स्टेडियम हॉस्टल से नेशनल टेबल टेनिस खिलाड़ी लापता...सीसीटीवी बंद मिले,पुलिस कर रही जांच

आगरा,01 अगस्त 2026।

आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम के हॉस्टल से राष्ट्रीय स्तर के टेबल टेनिस खिलाड़ी वंश सिंह संधिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। काफी तलाश के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरे बंद मिले, जिसके बाद पुलिस अब स्मार्ट सिटी के कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।



चार साल से हॉस्टल में रहकर कर रहे थे अभ्यास

वंश सिंह शाहगंज के नगला छऊआ के रहने वाले हैं और पिछले चार वर्षों से एकलव्य स्टेडियम के हॉस्टल में रहकर टेबल टेनिस की ट्रेनिंग ले रहे थे। वह अंडर-17 की कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं और कई पदक भी जीत चुके हैं। उनके बड़े भाई ध्रुव सिंह भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं।

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

वंश के पिता शैलेश सिंह का आरोप है कि गुरुवार को स्टेडियम प्रशासन ने बेटे के झगड़े की जानकारी देकर हॉस्टल से हटाने की बात कही थी। शुक्रवार सुबह जब वे हॉस्टल पहुंचे तो बताया गया कि वंश सुबह करीब 5 बजे बिना बताए कहीं चला गया। परिजनों का आरोप है कि हॉस्टल के एक अधिकारी और कर्मचारी ने वंश के साथ मारपीट की थी, जिससे वह मानसिक तनाव में था। क्षेत्रीय क्रोडा अधिकारी संजय शर्मा ने कहा कि वंश बिना सूचना दिए हॉस्टल से चला गया था। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य के कारण सीसीटीवी कैमरे बंद थे और मारपीट की जानकारी उन्हें नहीं है। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि खिलाड़ी की तलाश के लिए टीम लगाई गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और स्टेडियम कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी।

आज से कर्मशियल एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए सस्ता



नई दिल्ली,01 अगस्त 2026। केंद्र सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपये से ज्यादा की कटौती की है। नई कीमतों आज लागू हो गई हैं। पिछले कुछ समय से महंगी रसोई गैस की वजह से बढ़ते खर्च का सामना कर रहे कारोबारियों को इस फैसले से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नई दरों के मुताबिक दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 202 रुपये सस्ता हुआ है। इसके बाद राजधानी में इसकी नई कीमत 2,728 रुपये हो गई है। वहीं कोलकाता में सिलेंडर की कीमत 209 रुपये घटाई गई है, जिसके बाद वहां इसकी नई कीमत 2,872.50 रुपये तय की गई है। हालांकि यह राहत सिर्फ व्यावसायिक इस्तेमाल वाले सिलेंडरों तक सीमित है। घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को पहले वाली कीमत पर ही सिलेंडर मिलता रहेगा। पिछले कुछ महीनों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, ईरान युद्ध और आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतें बढ़ गई थीं। इसका असर भारत में भी कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों पर पड़ा था। होटल, रेस्तरां और कैटरिंग जैसे कारोबारों में रसोई गैस पर हर महीने अच्छा-खासा खर्च होता है। ऐसे में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटने से इन कारोबारों की लागत कम होगी और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। माना जा रहा है कि इस फैसले से होटल और फूड सर्विस से जुड़े कारोबारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हाल के दिनों में भारत ने अमेरिका और दूसरे देशों से स्पॉट आधार पर एलपीजी की खरीद बढ़ाई है, ताकि मध्य पूर्व से कम हो रही सप्लाई की भरपाई की जा सके।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बाद दर्शन व्यवस्था में बदलाव,अब ट्रस्ट के 3 सीए को भी मिला ये अधिकार

अयोध्या,01 अगस्त 2026। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में वीआईपी और विशेष श्रेणी के दर्शन पास को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितता के मामले के बाद कुछ समय के लिए पास दर्शन की सुविधा पर रोक लगाई गई थी। अब इसे दोबारा शुरू किया गया है, लेकिन पास जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था का उद्देश्य दर्शन पास प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है।

तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट की निगरानी में जारी होंगे पास : नई व्यवस्था के तहत ट्रस्ट के तीन अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट को दर्शन पास जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है। इनकी आधिकारिक आईडी के माध्यम से वीआईपी और विशेष श्रेणी के दर्शन पास उपलब्ध कराए जा सकेंगे। ट्रस्ट का मानना ​​है कि इससे पास जारी करने की प्रक्रिया पर निगरानी मजबूत होगी और अनधिकृत हस्तक्षेप या दुरुपयोग की आशंका कम होगी।

‘सुगम दर्शन’ की सुविधा भी रहेगी जारी : वीआईपी पास के साथ ‘सुगम दर्शन’ की सुविधा भी जारी रहेगी। इसके लिए तय प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। पास व्यवस्था में प्रशासनिक बदलाव के तहत जिम्मेदारी से जुड़े अधिकारियों और सदस्यों



रोजाना करीब 1800 पास का प्रावधान

राम मंदिर में दर्शन पास के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग का अलग कोटा भी निर्धारित है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, रोजाना करीब 1,800 पास छह अलग-अलग समय स्लॉट में जारी किए जाते हैं। प्रत्येक स्लॉट लगभग दो घंटे का होता है और उसमें करीब 300 श्रद्धालुओं को शामिल किया जा सकता है। वीआईपी और सुगम दर्शन के पास भी इन्हीं निर्धारित स्लॉट के अनुसार जारी किए जाते हैं।

पैसे देकर वीआईपी पास देने की व्यवस्था नहीं

मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए पैसे देकर पास खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है। विशेष दर्शन पास अधिकृत व्यक्तियों की सिफारिश और निर्धारित प्रक्रिया के तहत जारी किए जाते हैं। ट्रस्ट के अधिकृत लोगों के अलावा जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, डीआईजी और मंडलायुक्त स्तर के अधिकारियों को भी पास जारी करने का अधिकार दिया गया है।

में भी परिवर्तन किया गया है। ट्रस्ट से जुड़े व्यवस्था प्रभावित न हो, इसे ध्यान में रखते पूर्व पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद दर्शन हुए नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं।

आंध्र प्रदेश में भोगपुरम एयरपोर्ट समेत 18 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स शुरू,अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम से जोड़ा

पहले एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार पर थे हमने बदली परंपरा : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

अमरावती,01 अगस्त 2026।

पीएम मोदी ने शनिवार को आंध्रप्रदेश के अमरावती में कहा, ‘देश में पहले एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के नाम पर होते थे, लेकिन हमारी सरकार ने इस परंपरा को बदल दिया।’ उन्होंने कहा, ‘हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम बाल्मीकी के नाम से जोड़ा। पंजाब में एयरपोर्ट का नाम संत रविदासजी के नाम पर रखा। इस एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा है।’ पीएम ने यहां भोगपुरम एयरपोर्ट समेत 18 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

पीएम ने कहा...आज आंध्र प्रदेश में डबल स्पैड से काम हो रहा

पीएम ने कहा...आज चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के नेतृत्व में एनडीए की पूरी टीम आंध्र प्रदेश

के लिए डबल स्पैड से काम कर रही है। आंध्रप्रदेश में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। राज्य के पूरे रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। यहां 70 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है।

पीएम ने कहा...अल्लूरी सीताराम ने आदिवासियों के लिए काम किया...

मोदी ने कहा...कि ये अल्लूरी सीताराम राजू की धरती है। अल्लूरी सीताराम ने जिस धरती पर आदिवासी हितों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, आज वहां पर आंध्र प्रदेश के एक नए एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है। ये एयरपोर्ट आंध्र और उत्तर आंध्र की ग्रोथ का रनवे है। ये आंध्र के युवाओं के बेहतर भविष्य का लॉन्चपैड है।



पीएम बोले...12 साल में एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर 166 हुई

प्रधानमंत्री ने कहा...कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की है,इस पर भी 29 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुछ दिन पहले काशी में स्पोर्ट्स एयरपोर्ट मॉडल का शुभारंभ हुआ। आज वहीं मॉडल के पंजाब के अमृतसर तक पहुंच गया है। इससे अमृतसर से 25 से ज्यादा डेस्टिनेशन जुड़ जाएंगे।

मोदी बोले...पहले एक परिवार के नाम पर एयरपोर्ट होते थे...

पीएम ने कहा...पहले एयरपोर्ट ने नाम एक ही परिवार के नाम पर होते थे। हमने इस परंपरा को बदला। हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम बाल्मीकी के नाम से जोड़ा। पंजाब में एयरपोर्ट का नाम संत रविदासजी के नाम पर रखा,और इस एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा।

एनएच-37 हड़ताल से थमी तेल सप्लाई,पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लाइनें

मणिपुर,01 अगस्त 2026।

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक बार फिर ईंधन संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर तेल टैंकरों की आवाजाही पूरी तरह रुकने के बाद राजधानी इंफाल सहित राज्य के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। हालात ऐसे हैं कि पेट्रोल पंपों के बाहर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बड़ी संख्या में लोग संभावित कमी की आशंका को देखते हुए पहले से ही अपने वाहनों में ईंधन भरवाने पहुंच रहे हैं। इससे कई पेट्रोल पंपों पर घंटों इंतजार की स्थिति बन गई है और आम लोगों में भविष्य की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।



ऑपरेटरों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक वे इंफाल-जिरोंबाम मार्ग पर ईंधन की डुलाई शुरू नहीं करेंगे। इस फैसले का असर पूरे राज्य की ईंधन आपूर्ति पर पड़ना शुरू हो गया है।

सरकार को पहले ही दिया गया था अल्टीमेटम : ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि उसने इस मुद्दे को अचानक नहीं उठाया। संगठन ने 15 जुलाई को ही मणिपुर सरकार को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया था और समाधान के लिए 15 दिनों का समय दिया था। इसके बाद 29 जुलाई को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी

260 मौतों वाले ईस्टर ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला...पूर्व आईजीपी और रक्षा सचिव को फांसी,खुफिया जानकारी के बाद भी नहीं हुई थी कार्रवाई

कोलंबो,01 अगस्त 2026।

श्रीलंका की हाईकोर्ट ने 2019 के ईस्टर संडे आतंकी हमलों को रोकने में लापरवाही बरतने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। तीन सदस्यीय बेंच ने पूर्व पुलिस महानिरीक्षक पुजित जयसुरदा और तत्कालीन रक्षा सचिव हेमासिरी फर्नांडो को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि दोनों



अधिकारियों को हमलों से पहले खुफिया चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए। अदालत के

अनुसार, 20 अप्रैल 2019 की शाम तत्कालीन स्टेट इंटेलिजेंस सर्विस के प्रमुख निलंथा जयवर्धने ने जयसुरदा को जानकारी दी थी कि अगले दिन कैथोलिक चर्चों और प्रमुख होटलों पर आत्मघाती हमला हो सकता है। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं की गई और हमले को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। दो

न्यायाधीशों ने बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि दोनों अधिकारियों ने अपने संवैधानिक और प्रशासनिक दायित्वों की अनदेखी की, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान गई।

हालांकि, तीसरे न्यायाधीश ने असहमति जताते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया।

देश में लागू हुआ एंटी-पेपर लीक कानून राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी,अधिसूचना जारी

नई दिल्ली,01 अगस्त 2026। सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा में धोखेबी रोकने के लिए लाया गया पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस) संशोधन विधेयक, 2026 अब कानून बन गया है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को इसे मंजूरी दे दी है। कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को राजपत्र (गजट) अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। नए कानून के तहत पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के लिए पहले से अधिक सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य की रक्षा करना और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाना है।इस संशोधन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा ने पारित किया था। दोनों सदनों से पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ यह कानून लागू हो गया है। संशोधित कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा का पेपर लीक करता है या परीक्षा में अनुचित तरीके अपनाने का दोषी पाया जाता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक जुर्माने की सजा हो सकती है। वहीं, यदि पेपर लीक किसी संगठित गिरोह या नेटवर्क की ओर से किया जाता है, तो दोषियों को कम से कम 7 साल की जेल होगी। इसके अलावा 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।



छात्रों को पीएम की माफी की जरूरत नहीं,बल्कि उन्हें स्टूडेंट्स से माफी मांगनी चाहिए : राहुल चेन्नई,01 अगस्त 2026। राहुल गांधी ने शनिवार को चेन्नई में स्टूडेंट्स से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- स्टूडेंट्स को पीएम की माफी की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें स्टूडेंट्स से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि माता-पिता को अपने बच्चे का शोक मनाते देखने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। नीट पेपर लीक के बाद न पीएम पीडिआ माता-पिता से मिलें और न ही किसी ऐसे छात्र के साथ बैठें जिसका भविष्य पेपर लीक के कारण छिन गया। दरअसल, शुक्रवार रात 11 बजे राहुल ने पीएम पर एक वीडियो जारी कर कहा था कि जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ बच्चों ने उन्हें और उनकी मां को भेदी गालियां दीं। लेकिन वह उन बच्चों को माफ करते हैं क्योंकि बचपन गलती सुधारने का समय होता है। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि परिसीमन, तमिलनाडु के लोगों से मताधिकार छीनने की साजिश है।



राहुल गांधी,पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर केस दर्ज,भगवा वेश प्रदर्शन पर कार्रवाई

नई दिल्ली,01 अगस्त 2026। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई संसद भवन परिसर में हुए एक राजनीतिक प्रदर्शन को लेकर की गई है। शिकायत के आधार पर वाराणसी के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। पुलिस का कहना है कि प्राप्त शिकायत के आधार पर नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है और आगे की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।



राम मंदिर चढ़ावा मुद्दे पर हुआ था प्रतीकात्मक प्रदर्शन : संसद परिसर में विपक्षी नेताओं ने राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित मुद्दे को लेकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया था। इस दौरान सांसद पप्पू यादव भगवा वेशभूषा में दिखाई दिए और उनके पास एक प्रतीकात्मक दान पात्र भी रखा गया था। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने उस दान पात्र में कुछ रुपये डाले, जिसके बाद पप्पू यादव वहां से भागते हुए नजर आए। इस पूरे प्रदर्शन के माध्यम से विपक्ष ने राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े अपने आरोपों को प्रतीकात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया।

संत समाज ने जताई कड़ी आपत्ति : इस प्रदर्शन को लेकर वाराणसी के कई संतो और धार्मिक संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना है कि भगवा वेशभूषा को इस प्रकार के राजनीतिक प्रदर्शन में इस्तेमाल करना संत परंपरा और धार्मिक प्रतीकों की गरिमा को अनुरूप नहीं है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इस प्रदर्शन से करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। संत समाज ने पुलिस से मामले

में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। **धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप :** कोतवाली थाने में दर्ज शिकायत में राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि भगवा वेश पहनकर चोरी का प्रतीकात्मक दृश्य प्रस्तुत करना अनुचित है और इससे धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंची है। हालांकि, मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और आरोपों की सत्यता का परीक्षण जांच के दौरान किया जाएगा। **भाजपा और बिस्व हिंदू परिषद ने भी उठाए सवाल :** भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और बिस्व हिंदू परिषद सहित कई संगठनों ने भी इस प्रदर्शन की आलोचना की है। इन संगठनों का कहना है कि भगवा वस्त्रों को चोरी जैसे प्रतीकात्मक दृश्य से जोड़ना हिंदू समाज की भावनाओं का अपमान है। भाजपा नेताओं ने इसे धार्मिक प्रतीकों के अनुचित उपयोग का मामला बताया, जबकि बिस्व हिंदू परिषद ने भी इस तरह के प्रदर्शन पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की।

संपादकीय



समान नागरिक संहिता : संवैधानिक संकल्प सामाजिक संवाद और राजनीतिक चुनौती

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड-यूसीसी) का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति गठित किए जाने के बाद राज्य में इस विषय पर गंभीर बहस शुरू हो गई है। उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस विषय पर भावनाओं के बजाय तथ्यों, संविधान और समाज की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर चर्चा हो। भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि यह मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि नीति-निर्देशक सिद्धांत है, फिर भी संविधान निर्माताओं की यह सोच थी कि भविष्य में देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे नागरिक मामलों में समान कानून हो। सात दशक बाद भी यह विषय पूरी तरह लागू नहीं हो सका है, क्योंकि भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता इसे जटिल बनाती है।

यूसीसी के समर्थकों का तर्क है कि अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण समानता का सिद्धांत प्रभावित होता है। उनका मानना ​​है कि एक समान नागरिक कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान कानूनी संरक्षण मिलेगा। विशेष रूप से महिलाओं के अधिकार, उत्तराधिकार में समानता, विवाह और तलाक से जुड़े मामलों में न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। उनका कहना है कि जब आपराधिक कानून पूरे देश में समान हो सकते हैं, तो नागरिक कानूनों में भी समानता स्थापित की जा सकती है।

वहीं दूसरी ओर, इस विषय को लेकर कई सामाजिक, धार्मिक और जनजातीय संगठनों की चिंताएं भी सामने आती रही हैं। उनका कहना है कि भारत केवल विभिन्न धर्मों का देश नहीं, बल्कि अनेक संस्कृतियों, परंपराओं और सामाजिक व्यवस्थाओं का भी देश है। ऐसे में किसी भी कानून को लागू करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान या परंपरागत अधिकारों पर अनावश्यक प्रभाव न पड़े। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां बड़ी जनजातीय आबादी अपनी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था और रीति-रिवाजों के अनुसार जीवन जीती है, वहां यह प्रश्न और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

सरकार द्वारा गठित समिति के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह समाज के सभी वर्गों का विश्वास जीत सके। समिति यदि केवल औपचारिकता निभाएगी तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। लेकिन यदि वह विधि विशेषज्ञों, समाजशास्त्रियों, महिला संगठनों, जनजातीय प्रतिनिधियों, धार्मिक विद्वानों और नागरिक समाज के साथ व्यापक संवाद कर सुझावों के आधार पर प्रारूप तैयार करेगी, तो यह प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय और स्वीकार्य बन सकती है।

यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी बड़े कानूनी सुधार की सफलता केवल कानून बनने से नहीं होती। कानून तभी प्रभावी होता है जब समाज उसे न्यायपूर्ण और आवश्यक मानकर स्वीकार करे। भारत में अनेक सामाजिक सुधार व्यापक जनसंवाद और सहमति के बाद सफल हुए हैं। इसलिए यूसीसी पर भी संवाद का रास्ता ही सबसे उपयुक्त माना जाना चाहिए।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। समर्थक इसे संविधान के एक अग्रणी संकल्प को पूरा करने की दिशा में कदम मानते हैं, जबकि विरोधी इसे सामाजिक विविधता और व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े अधिकारों के संदर्भ में देखते हैं। ऐसे में सरकार को जिम्मेदारी और बड़ जाती है कि वह इस विषय को राजनीतिक बहस तक सीमित न रखे, बल्कि इसे संवैधानिक और सामाजिक सुधार के रूप में प्रस्तुत करे।

छत्तीसगढ़ में समिति का गठन एक प्रारंभिक कदम है। अब राज्य की जनता की निगाहें इस बात पर होंगी कि समिति का प्रारूप कितना संतुलित, व्यावहारिक और संवेदनशील होता है। क्या उसमें महिलाओं के अधिकारों को विशेष स्थान मिलेगा? क्या जनजातीय समाज की पारंपरिक व्यवस्था का सम्मान होगा? क्या सभी समुदायों से प्राप्त सुझावों को निष्पक्ष रूप से शामिल किया जाएगा? इन प्रश्नों के उत्तर ही इस पहल की सफलता तय करेंगे।

सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि समिति की कार्यवाही अधिकतम पारदर्शी हो। समय-समय पर सुझाव आमंत्रित किए जाएं, मसौदे के प्रमुख बिंदु सार्वजनिक किए जाएं और नागरिकों को अपनी राय रखने का अवसर मिले। इससे कानून बनने से पहले ही समाज में अनावश्यक भ्रम और आशंकाओं को दूर किया जा सकेगा।

समान नागरिक संहिता केवल कानून बदलने का विषय नहीं है, बल्कि यह संविधान की भावना, सामाजिक विविधता, लैंगिक न्याय और लोकतांत्रिक संवाद-इन सभी की परीक्षा है। यदि यह प्रक्रिया सहमति, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ती है, तो यह छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पहल साबित हो सकती है। लेकिन यदि संवाद की जगह जल्दबाजी या टकराव हावी हुआ, तो कानून बनने से पहले ही समाज में नई बहस और विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस विषय पर सबसे बड़ी आवश्यकता है-संवाद, संतुलन और संविधान की भावना के प्रति प्रतिबद्धता।

विचारधारा:जेन जी,अल्फा,नई जेनरेशन और समय परिवर्तन चक्र

देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर फिर एक और आंदोलन से चर्चा का विषय बना हुआ है। तथाकथित तथ्यों पर आधारित इसे जेन जी आंदोलन 2 कहा जा रहा है।अब विपक्ष और देश के युवा 20 जुलाई को हुई बर्बरता लाठीचार्ज,आर्स् गैस ,लडकियों से किये गए दुर्व्यवहार की

जवाबदारी के एवज में ग्रह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे है। उनका मानना है कि ये सब बर्बरता गृहमंत्री अमित शाह के आदेश से हुई है। आज देश में उठा युवाओं का एक आंदोलन प्रचण्ड ज्वाला का रूप ले चुका है। जो देश के हर कोने में दहक रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आवाम अब खुलकर मौजूदा सरकार के प्रतिनिधियों से 12 साल के कार्यकाल और किए गए वादों की जवाबदारी मांग रही है । आवाम में हुआ आक्रोश अब फूट रहा है। अब



युवाओं के साथ हर वर्ग और क्षेत्र का

सोशल मीडिया की अदालत : क्या मीड का फैसला ही अंतिम सत्य है?

डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह बदल गई है। आज के दौर में लगभग सभी लोगों के पास मोबाइल फोन है और कुछ ही सेकंड में कोई भी व्यक्ति अपने विचार पूरी दुनिया में साझा कर सकता है। सूचना का लोकतंत्रीकरण आधुनिक समाज की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, क्योंकि समाचार और विचार अब पारंपरिक संस्थानों तक ही सीमित नहीं हैं। लेकिन इस सशक्तिकरण में एक गंभीर खतरा भी छिपा है। आजकल तर्कपूर्ण बहस की जगह अधूरी जानकारी, अफवाहें, ऑनलाइन ट्रोलिंग और डिजिटल भीड़ के विचारों ने ले ली है। कई मामलों में, व्यूज, रेटिंग और वायरल होने की होड़ सच्चाई की खोज से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। महज कुछ घंटों में एक वीडियो ऑनलाइन आ जाता है, किसी मुद्दे का एक पक्ष सामने आता है, कुछ सोशल मीडिया अकाउंट उसे फैला देते हैं, और लाखों लोग बिना सबूत या उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी को दोषी घोषित कर देते हैं। सोशल मीडिया की यह तत्काल अदालत न तो तथ्यों की समीक्षा करती है और न ही निष्पक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करती है। इसने अक्सर अन्यायपूर्ण तरीके से, भावनाओं, अधूरी सच्चाइयों और भीड़ की मानसिकता के आधार पर फैसले सुनाए हैं।



पक्ष की बात सुनने को भी तैयार होंगे? क्या वे यह स्वीकार करेंगे कि उनसे जल्दबाजी में फैसला लेने की संभावना हो सकती है? लेकिन क्या रुझान, आक्रोश और ऑनलाइन लोकप्रियता सच्चाई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बने रहेंगे?

भारतीय न्याय प्रणाली का एक मूलभूत पहलू यह है कि निर्दोषता का सिद्धांत भारतीय न्यायालयों में एक सार्वभौमिक नियम है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है। यह कोई कानूनी तर्क-वितर्क नहीं, बल्कि किसी भी सभ्य समाज का मूलभूत सिद्धांत है। जब इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, तो न्याय के स्थान पर अराजकता फैल जाती है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से जन आक्रोश का शिकार हो सकता है।

ट्रोलिंग सिर्फ आलोचना तक सीमित नहीं है, यह ऑनलाइन होती है। इसका इस्तेमाल अक्सर सार्वजनिक दंड के रूप में किया जाता है। लोग लाइक्स, शेयर्स और व्यूज के नाम पर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, करियर, परिवार और भविष्य को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दशकों की अच्छी प्रतिष्ठा पल भर में नष्ट हो सकती है। अदालत में निर्दोष साबित होने पर भी सामाजिक कलंक अक्सर मिटता नहीं है।

तो फिर एक अहम सवाल उठता है। झूठे आरोप में फंसे व्यक्ति को सम्मान कौन दिलाएगा? क्या वायरल पोस्ट को हटाने से लोगों की याददाश्त मिट जाएगी? क्या सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के बाद व्यक्ति पश्चाताप करेगा, या उसे भुला दिया जाएगा? ज्यादातर मामलों में, ऐसा नहीं होता। कानूनी तौर पर निर्दोष साबित होने से समाजिक क्षति की पूरी तरह भरपाई नहीं हो सकती।

हालांकि, यह बात भी बेहद महत्वपूर्ण है कि असली अपराधियों के प्रति कोई सहनशुभ्रित नहीं होनी चाहिए। महिलाओं,

बच्चों या छात्रों की गरिमा और सुरक्षा से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कानूनी सजा लगाई जानी चाहिए। न्याय अवश्य होना चाहिए, चाहे वह निर्दोष ही क्यों न हो, और दोषियों को कठोर दंड मिलना चाहिए। न्याय का अर्थ केवल अपराध को दंडित करना ही नहीं है; इसमें उन लोगों की रक्षा करना भी शामिल है जिन पर गलत आरोप लगाए गए हैं। परंपरागत मीडिया और सोशल मीडिया की प्रतिस्पर्धा ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। सबसे पहले खबर देने की होड़ में अक्सर तथ्यों की पुष्टि नहीं हो पाती। सुर्खियों का उद्देश्य पाठक की भावनाओं को भड़काना होता है। यदि बाद में कोई घटनाक्रम मूल रिपोर्ट के विपरीत साबित होता है, तो सुधारों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। परिणामस्वरूप, गलत सूचना लाखों लोगों तक फैल जाती है जबकि सच्चाई उतनी देर तक नहीं पहुंच पाती।

दुनिया को यह समझने की जरूरत है कि वास्तव होने वाली कोई भी चीज हमेशा सही नहीं होती। मूल संदर्भ से अलग की गई सामग्री और जानकारी, कुछ सेकंड का वीडियो या एक अलग विषय, जनमत को इस्तेमाल अक्सर सार्वजनिक दंड के रूप में किया जाता है। सोचना और सत्यापित तथ्यों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है।

परंपरागत रूप से, भारतीय समाज में शिक्षकों को भरोसेमंद और सम्मानित माना जाता है। जब कोई शिक्षक आपराधिक कृत्य द्वारा इस भरोसे को तोड़ता है, तो समाज को सख्त होना चाहिए क्योंकि यह न केवल कानून का, बल्कि जनता के भरोसे का भी उल्लंघन है। हालांकि, जब कोई शिक्षक झूठे आरोपों का शिकार होता है, तो यह समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि शिक्षण पेशे की गरिमा का भी मामला बन जाती है। इसलिए लोगों के निर्णय सबूतों पर आधारित होने चाहिए, न कि भावनाओं पर।

अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया को सकारात्मक चर्चा के मंच के

भारतीय खड़ा दिखाई दे रहा है। शिक्षा से लेकर युवाओं की अन्य कई समस्या है । आज अधिकांश युवा बेरोजगारी की चपेट में है । अच्छे दिनों की राह देखते देखते लोगों की आंखें पथरा गई है । आर्थिक तंगी ने लोगों का स्कून खत्म कर दिया है । जनता की मूलभूत जरूरतें महंगाई के चरम पर है । राम मंदिर की चोरी ने जनता की आस्था को आहत किया है। जनता का सरकार, व्यवस्था के प्रति विश्वास हिल दिखवाई देता है। शायद अब देश के युवा पढ़े लिखे प्रतिनिधियों

को चुनना चाहते है जो उनकी आवाज को सुने और नए तरीके अपनाते हुए समानता से हर कानून कायदे को लागू करें। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि निधियों का चयन चाहती है। वह मीडिया या लोकतंत्र पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं चाहती है। समय एक नई लहर का है । जमाना जेन जी,अल्फा और आने वाली नई जेनरेशन का है । युवा देश का भविष्य है और परिवर्तन समय चक्र का नियम।

दुनिया में ऐसा छाँव है कहाँ



अशोक पटेल आरु शिवरीनारायण, छत्तीसगढ़

दुनिया में ऐसा छाँव कहाँ, जहाँ मैं सुकून पाऊँ दुनिया में ऐसा गोद कहाँ, जहाँ चैन से सो पाऊँ ऐसा कोई और नहीं, बस तेरा मैं सानिध्य पाऊँ माँ से बड़कर ऐसा और कहाँ, मैं ये जन्नत पाऊँ।

माँ के चरणों में सारी दुनिया का, मैं प्यार पाऊँ रूठ जाऊँ मैं कितना भी, तो भी मनुहार पाऊँ ऐसा कोई और नहीं, तेरे आँचल का छाँव पाऊँ ददं स्वयं लेने वाली, ऐसी माँ का उपकार पाऊँ।

माँ दयालू है, ममतामयी है, तेरा आशीष पाऊँ तेरे चरणों में समर्पित होऊँ, नीत शीश झुकाऊँ मैं बेसहारा, जग का मारा, बस तेरा सहारा पाऊँ मन हुआ है अधीर मेरा, बस तेरा आसरा पाऊँ।

क्या मेरा अस्तित्व है, बस जरा सा मान पाऊँ तन समर्पित, मन समर्पित, मैं तेरा सम्मान पाऊँ पानी की बुलें जैसी, श्रद्धा सागर में मिले जाऊँ तुझसे दुक़र माँ कहाँ है, जिसका मैं गुण गाऊँ।

वक्त के महत्व को समझें

वक्त के महत्व को समझें, क्योंकि वक्त बहुत ही मूल्यवान होता है। एक बार जो वक्त बीत जाता है, वो कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए हम सभी को वक्त की कद्र करनी चाहिए, अन्यथा हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। जिंदगी के सफर में सब कुछ निश्चित समयावधि के अनुसार ही होता है। समय पर बोया हुआ बीज ही फसल देता है, समय पर पढ़ा हुआ छात्र ही परीक्षा में सफल होता है और जिंदगी कैसे जीना है, ये बात हर ईंसान को खुद तय करनी होगी। आलस्य करने वाले समय के महत्व को नहीं समझते, वहीं मेहनती समय के साथ वक़्त लगाकर आगे निकल जाते हैं। क्योंकि जिंदगी में हर किसी को एक सुअवसर जरूर मिलता है। जो इस



अवसर को समझकर समय के साथ चलते हैं, वो आसमान को छूने से नहीं डरते। वहीं समय से विलंब चलने वाले जमीन पर रहने से भी डरते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब - घड़ी की सुई सबके लिए एक ही गति से चलती है। इसलिए आज से ही हम सभी को एक वचन खुद से लेना चाहिए कि हम अपने जीवन का एक-एक पल को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। समय का सही उपयोग करके सफलता की शिखर पर पहुँचेंगे और कहेंगे है ना-जो वक्त को समझ गया, मानो जिंदगी जीत गया।

प्रेम-डोर



डॉ. प्रियंका सौरभ हिसार, हरियाणा

प्रेम-डोर जब थाम ली, जुड़ते सकल जहान। अहं तनिक जो बीच में, उजड़ै सब उद्यान॥ धोके के दो छोर हैं, दो जीवन के द्वार। एक संभाले याद को, दुजा दे विस्वार॥ कपन-कपन कह रहा, जीवन रचा विधान- प्रेम-डोर जब थाम ली, जुड़ते सकल जहान॥ खींचा यदि अहंकार ने, टूटी हर पहचान॥ जीत एग शब्दों मगर, हर गया ईंसान॥

झुककर जिसने बाँध ली, वहीं रहता महान- प्रेम-डोर जब थाम ली, जुड़ते सकल जहान॥ प्रेम न केवल भाव है, जीवन का आधार। सुखे मन में भी जगा, हरियाला संसार॥ बाँट सका जो नेह को, पाया अमृत-दान प्रेम-डोर जब थाम ली, जुड़ते सकल जहान॥ विश्वासों की ऊँचाईयें, थामे जब विश्वास। अदृश्यों में दिखने लगे, सृष्टि-हृदय के पास॥ ब्रह्मांड की डोर भी, प्रेममयी पहचान- प्रेम-डोर जब थाम ली, जुड़ते सकल जहान॥



डॉ. मुस्ताक अहमद हदद, मध्यप्रदेश

प्रकृति के इन मूक रश्मियों, आदि-काल से अडिग खड़े विराट महाशिवरॉय और अपनी अनंत हरी छांव में सदियों से एक गहरा, रहस्यमयी मौन सांथे इन वीर वनों के अंतहीन साम्राज्य के बीच पसरी यह जादुई और सम्मोहक शक्ति वास्तव में कोई निर्वात या रिता शून्य नहीं है, बल्कि यह तो संपूर्ण ब्रह्मांड का वह अनाहत नाद और आदि-संगीत है जो केवल और केवल आत्मा की गहनतम गहराइयों में ही तब सुनाई देता है, जब हम आधुनिकता की अंधी चकाचौंध, शहरों की इस मशीनी, प्रणहीन और थका देने वाली अंधी दौड़, कृत्रिमता के आडंबरों और ईसानी बस्तियों के कभी न धमने वाले अंतहीन शोर-शराबे से पूरी तरह टूटकर और थककर इन पर्वतीय अंचलों के इतने आत्मीय करीब आते हैं कि देवदार और चीड़ के पेड़ों की मखमली, ओस-भीगी हरी पत्तियों के सहलाते हुए उनके निर्नात एकान्त, उनकी सदियों पुरानी अनखड़ी दास्तां, उनके भीतर छुपे आदिम दर्द और उनकी नीरव भाषा को साक्षात् महसूस कर सकें, क्योंकि ठीक उसी पावन क्षण में हमारे भीतर भीतिकता की नींद में सोया हुआ मनुष्य और परम संवेदना का भावुक कवि एक साथ जाग उठता है। यह वह परम पवित्र और अलौकिक धरा है जहाँ नीले गगन के असीम विस्तार को छूते ये अभेद्य, ऊंचे बफीले शिखर अपनी अचलता से हमें यह महान जीवन-दर्शन सिखाते हैं कि वक्त के क्रूर से क्रूर कड़े थपेड़ों, झंझावातों और मौसम के हर बदलते मिजाज को बिना विचलित हुए अगाध धीरज के साथ सहकर भी अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान और अपनी मूल सांस्कृतिक जड़ों पर किस प्रकार मजबूती से अडिग रह जाता है, और वहीं दूसरी ओर, इन विशालकाय पहाड़ों का सीना चीरकर, पथरों की छतों को बेधकर जब कलकल-छलछल करते चरभे, ऊंचाइयों से गिरते दुग्ध-धवल झरने और वेगवती नदियाँ अपनी संपूर्ण अलौकिक ऊर्जा के साथ बाहर फूटती हैं, तो वे केवल पानी का कोई भीतिक बहाव मात्र नहीं



होंती, बल्कि वे साक्षात् वसुंधरा के धड़कते हुए हृदय की जीवंत धड़कन बन जाती हैं; जो अपने उदगम से लेकर मैदानों की ओर बढ़ने की इस दुर्गम और अत्यंत कठिन यात्रा में जब मार्ग में आड़े आने वाली विशालकाय चट्टानों, तीखे मोड़ों और कठोर पत्थरों से बार-बार टकराती हैं, तो यह भीषण टकराव किसी प्रलयकारी विनाश या कोलाहल को नहीं, बल्कि एक अतीव मधुर, कर्णप्रीय और रूहानी कलकल-छलछल के आदि-संगीत को जन्म देती है, और ऐसा रूप लेती है मानो ये नदियाँ उन निष्ठुर पत्थरों से टकरा-टकराकर, उन्हें गलुगलुती और ताराशरक पूरे संसार को गुगुनाती हुई यह अमर और शाश्वत संदेश दे रही हैं कि जीवन का वास्तविक नाम कहीं भी उठरना या जड़ हो जाना नहीं है, बल्कि मार्ग की हर बड़ी से बड़ी बाधा, विपत्ति और अवरोध को ही अपनी शक्ति बनाकर, उसे काटकर अपना नया रास्ता बनाते हुए निरंतर, अबाध गति से आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि मुश्किलें और संघर्ष ईंसान को मिटाने या बिखरने के लिए नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे वास्तविक आत्म-सौंदर्य को निखारने और उसे कुंदन बनाने के लिए ही आती हैं। वनों की इस अत्यंत गहरी, शीतल और रहस्यमयी छाँव के साए में एक अद्भुत, अलौकिक और बिना किसी शर्त वाला निश्छल प्रेम तथा परस्पर सह-अस्तित्व का दिव्य साम्राज्य चारों ओर बिखरा पड़ा है, जहाँ छोटे-बड़े, कड़वे-मीठे, कटीले और छयादार हर प्रकार के पौधे और वनस्पति बिना किसी आंतरिक द्वेष, ईर्ष्या, शिकवे या किसी भी सामाजिक भेदभाव के एक साथ मिलकर पनपते हैं, फलते-फूलते हैं, और संपूर्ण जीव-जगत के कुल्याण के लिए, हवाओं को शुद्ध और प्राणदायिनी बनाने के लिए वातावरण के सारे प्रदूषण और विष को खुद पी जाते

चाय की दुकान

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उत्तरुत्

शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर मन्ू की चाय की दुकान केवल एक गुमटी नहीं थी बल्कि उस पूरे इलाके की धड़कन थी जहाँ रोज सुबह से देर रात तक लोगों का तांता लगा रहता था। उस छोटी सी दुकान के कोने में लकड़ी की एक पुरानी बेंच रखी थी जहाँ हर शाम रामनाथ जी आकर बैठते थे। सफेद कुर्ता-पायजामा पहने और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी लिए रामनाथ जी जब भी आते तो मन्ू बिना कुछ पूछे मिट्टी के कुल्हड़ में कड़क अदरक वाली चाय उनके सामने रख देता था। रामनाथ जी चाय का केवल एक घूंट लेते और फिर उस आधे भरे कुल्हड़ को घंटे भर अपने हाथों में पकड़े टुकुर-टुकुर सामने की सड़क को निहारते रहते थे। मन्ू ने सालों से यह माजरा देखा था लेकिन उसने कभी उससे इस बात का कारण पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। एक दिन जब दुकान पर ग्राहकों की भीड़ कुछ कम हुई तो मन्ू से रहा नहीं गया और वह हाथ में पोछा लिए उनके पास जाकर झुड़ा हो गया। मन्ू ने बहुत ही सहेज कर अपनी बात रखते हुए पूछा -बाबूजी आप रोज आते हैं और इतनी बर्दथा गरम चाय का बस एक घूंट पीकर छोड़ देते हैं, बाकी की पूरी चाय ठंडी होकर बेकार हो जाती है, क्या हमारी चाय का स्वाद आपको पसंद नहीं आता या फिर कोई और बात है? रामनाथ जी ने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हाथों से उस कुल्हड़ को सहलाते हुए मुस्कुराए। उनकी आँखों में एक अजीब सी चमक तैर गई और उन्होंने धीमी आवाज में कहा -मन्ू भाई इस कुल्हड़ की मिठास तो सुझे उस राह पर ले जाती है जहाँ मेरा पूरा संसार बसा हुआ है। रामनाथ जी की बात सुनकर मन्ू की उत्सुकता और बढ़ गई क्योंकि उसे लगा कि शायद किसी पुराने प्यार या खोए हुए रिश्ते की कहानी अब बाहर आने वाली है। उन्होंने आगे बोलना शुरू किया मन्ू तुम्हें शायद पता नहीं है कि यह आधा भार कुल्हड़ की ही आदत पड़ गई है। मन्ू के चेहरे पर एक हसदंवी भरी मुस्कान आ गई और उसने कहा अच्छा तो बाबूजी आप यहाँ बैठकर अपने साहबजादे का इंतजार करते हैं कि वह किसी दिन आएगा और आपके साथ बैठकर यह आधी बची हुई चाय पूरे हक से पिपाए। रामनाथ जी की आँखों में चमक आ गई और उन्होंने फिर हिलाकर हँ में जवाब दिया।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं : छत्तीसगढ़ में अमानक पनीर और भ्रामक डेयरी एनालॉग उत्पादों पर सख्त प्रतिबंध

राजपत्र में अधिसूचना जारी...अब नकली दूध जैसे उत्पादों के निर्माण से लेकर बिक्री तक पर रोक...

- स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल, उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम...
- स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं : छत्तीसगढ़ में भ्रामक डेयरी एनालॉग उत्पादों पर बड़ा प्रहार...
- राज्य सरकार ने लागू किया प्रतिबंध,अब नकली 'दूध जैसे' उत्पादों की बिक्री पर सख्ती...
- कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल... उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय

-रवि सिंह-
रायपुर/एमसीबी,01 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है,राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में ऐसे डेयरी एनालॉग अथवा गैर-दुध किंतु दुग्ध उत्पादों के समान दिखने वाले खाद्य पदार्थों के निर्माण,प्रसंस्करण,भंडारण,परिवहन, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है,जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं,लेकिन अपनी पैकेजिंग, लेबलिंग अथवा प्रस्तुति के माध्यम से उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी 31 जुलाई 2026 के छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में इस संबंध में अधिसूचना प्रकाशित की गई है,आदेश के अनुसार यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(क) एवं धारा 18 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए की गई है, यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब बाजार में दूध,पनीर,ची, मक्खन,क्रीम और अन्य डेयरी उत्पादों के नाम पर बड़ी संख्या में ऐसे उत्पाद बेचे जा रहे हैं, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल अथवा अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया जाता है,ऐसे उत्पाद कई बार अपनी पैकेजिंग और प्रस्तुति से उपभोक्ताओं को भ्रमित कर देते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पहले ही दिए थे सख्त संकेत

राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा,पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रिया-व्ययन मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पूर्व में ही

क्या है डेयरी एनालॉग उत्पाद?

डेयरी एनालॉग ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो देखने,पैकिंग और नाम से दूध,पनीर,ची,मक्खन या अन्य दुग्ध उत्पादों जैसे प्रतीत होते हैं,लेकिन वास्तव में इनमें दूध की जगह वनस्पति वसा,वनस्पति तेल या अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया जाता है,ऐसे उत्पाद यदि स्पष्ट रूप से अपनी वास्तविक पहचान नहीं बताते और उपभोक्ता को भ्रमित करते हैं तो यह खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकारों दोनों के लिए गंभीर चुनौती बन जाते हैं।

किन उत्पादों पर रूढ़िवा प्रतिबंध?

राजपत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध विशेष रूप से उन उत्पादों पर लागू होगा जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं,जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल अथवा अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया गया है,जिनकी पैकेजिंग,लेबलिंग अथवा प्रस्तुति उपभोक्ता को यह विश्वास दिलाती है कि वह वास्तविक दुग्ध उत्पाद खरीद रहा है,ऐसे उत्पाद जिनकी बिक्री भ्रामक तरीके से की जाती है,हालांकि फ्रोजन डेजर्ट,प्रोसेस्ड चीज और मिक्सड फैट स्मैड जैसे वे उत्पाद, जो नियमानुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं और जिनकी सही लेबलिंग की गई है,इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रहेंगे।

स्पष्ट कर दिया था कि जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेशवासियों को सुरक्षित, शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में अब सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है,मर्नेटगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री श्री जायसवाल लगातार खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय प्रदेश में खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण को नई दिशा देगा।

किन उत्पादों को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है?

राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ उत्पाद इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके लिए अलग खाद्य मानक निर्धारित

हैं,इनमें शामिल हैं फ्रोजन डेजर्ट,प्रोसेस्ड चीज, मिक्सड फैट स्मैड बशर्ते वे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्धारित मानकों का पालन करते हों और उनकी लेबलिंग पूरी तरह स्पष्ट एवं नियमानुसार हो।

स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ पर सरकार की सख्ती

विशेषज्ञों का मानना है कि कई बार उपभोक्ता आकर्षक पैकेजिंग और नाम देखकर ऐसे उत्पाद खरीद लेते हैं, जिन्हें वे दूध या दुग्ध उत्पाद समझते हैं,जबकि वास्तविकता में उनमें दूध की मात्रा नगण्य होती है अथवा बिल्कुल नहीं होती,ऐसे उत्पाद बच्चों के पोषण को प्रभावित कर सकते हैं,बुजुर्गों और मरीजों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, उपभोक्ताओं के साथ आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी धोखा साबित हो सकते हैं,इसी खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने यह प्रतिबंध लागू किया है।

छत्तीसगढ़ में अमानक पनीर और डेयरी एनालॉग उत्पादों पर लगा प्रतिबंध

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की थी घोषणा

राज्य सरकार ने अमानक दुग्ध उत्पादों पर सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ की पूरी सीमा में ऐसे 'डेयरी एनालॉग' या गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, जो असली दूध उत्पाद होने का भ्रम पैदा करते हैं।



किन उत्पादों पर लागू होगा प्रतिबंध

- जो उत्पाद वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं
- जिनमें दूध की जगह वनस्पति वसा, वनस्पति तेल या अन्य गैर-दुग्ध सामग्री का उपयोग हो
- जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग या प्रदर्शन उपभोक्ताओं को गुमराह करता हो

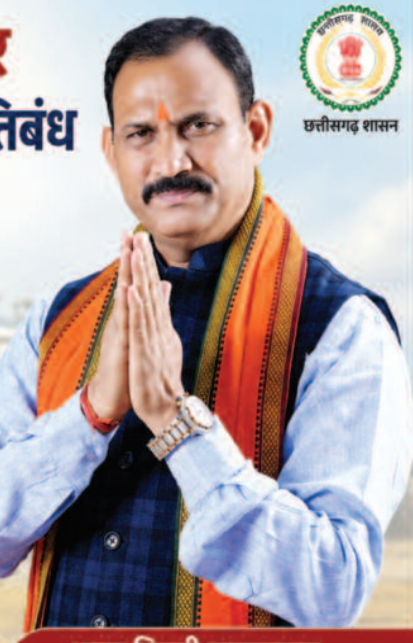
इन उत्पादों को मिली छूट

फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज और मिक्सड फैट स्मैड



सख्त कार्रवाई के निर्देश
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को पूरे प्रदेश में जांच अभियान चलाने के निर्देश, नियम तोड़ने वालों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दण्ड होगी कार्रवाई

उद्देश्य : उपभोक्ताओं को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा भ्रामक उत्पादों से संरक्षण देना।



श्याम बिहारी जायसवाल

स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, 20 सूत्रीय कार्यक्रम

विधायक - मर्नेटगढ़, विधानसभा 02

अमानक पनीर पर विशेष फोकस

हाल के वर्षों में बाजार में बड़ी मात्रा में ऐसा पनीर उपलब्ध होने की शिकायतें सामने आती रही हैं जिसमें दूध के बजाय वनस्पति वसा अथवा अन्य सस्ते विकल्पों का उपयोग किया जाता है,ऐसे पनीर—पोषण की दृष्टि से कमजोर हो सकते हैं, उपभोक्ताओं के साथ धोखा साबित हो सकते हैं,बच्चों एवं मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं,इसी कारण सरकार ने विशेष रूप से अमानकीकृत पनीर जैसे उत्पादों पर सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है।

खाद्य कारोबारियों को सख्त चेतावनी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचना लागू होने के बाद किसी भी निर्माता, थोक व्यापारी,वितरक या विक्रेता द्वारा प्रतिबंधित उत्पादों का कारोबार पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी,खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को पूरे प्रदेश में विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं,निरीक्षण के दौरान—निर्माण इकाइयों की जांच होगी,गोदामों का निरीक्षण होगा,बाजार से नमूने लिए जाएंगे,प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता परीक्षण कराया जाएगा,दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत—राज्य सरकार ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए,अब संबंधित अधिकारी निर्माण इकाइयों की जांच करेंगे,गोदामों का निरीक्षण करेंगे, परिवहन और वितरण व्यवस्था पर नजर रखेंगे,बाजार में बिक रहे सदिग्ध उत्पादों के नमूने लेकर परीक्षण करेंगे, नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उठाया गया कदम—सरकार ने यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,2006 के तहत लिया है, अधिसूचना में कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसे उत्पादों का निरंतरण आवश्यक है जो अपनी प्रस्तुति के माध्यम से

उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं, राजपत्र के अनुसार यह प्रतिबंध अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो गया है और यह एक वर्ष अथवा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा इस विषय पर अंतिम मानक अधिसूचित किए जाने अथवा राज्य सरकार द्वारा आदेश में संशोधन/निरस्तीकरण किए जाने तक प्रभावी रहेगा।

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को मिलेगा नया आधार—खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है,इससे बाजार में नकली और भ्रामक डेयरी उत्पादों पर प्रभावी अंकुश लगेगा तथा लोगों को शुद्ध और मानक आधारित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

जनस्वास्थ्य सर्वोपरि

छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जा रहा है,आज जब बाजार में आकर्षक पैकेजिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले उत्पादों की संख्या बढ़ रही है,ऐसे समय में यह कदम लोगों को सुरक्षित,शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है,यदि इस आदेश का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन होता है तो निश्चित रूप से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी तथा उपभोक्ताओं का भरोसा भी बढ़ेगा।

मुख्य बिंदु (खंडलाइट्स)

- पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रामक डेयरी एनालॉग उत्पादों पर तत्काल प्रतिबंध।
- अमानक पनीर,क्रीम,मक्खन जैसे उत्पाद सरकार के ख़तर पर।
- दूध की जगह वनस्पति वसा का उपयोग कर भ्रम पैदा करने वाले उत्पादों पर सख्ती।
- निर्माण,भंडारण,परिवहन,वितरण और बिक्री—सभी पर रोक।
- खाद्य एवं औषधि प्रशासन करेगा विशेष जांच अभियान।
- स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल को जनस्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
- उद्देश्य—प्रदेशवासियों को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा उपभोक्ताओं को भ्रामक खाद्य उत्पादों से संरक्षण देना।

लोक परीक्षा संशोधन विधेयक युवाओं के हित में ऐतिहासिक कदम : शिवनाथ यादव

भाजपा प्रदेश मंत्री बोले...कठोर कानून से पेपर लीक और परीक्षा माफिया पर लगेगा प्रभावी अंकुश

पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और ईमानदार अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा को बनाया केंद्र सरकार की प्राथमिकता

-संवाददाता-

सूरजपुर,01 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

भाजपा जिला प्रभारी एवं प्रदेश मंत्री शिवनाथ यादव ने लोकसभा में पारित लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 का स्वागत करते हुए इसे देश के करोड़ों युवाओं के हित में एक ऐतिहासिक और दूरगामी कदम बताया है,उन्होंने कहा कि यह संशोधन प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, प्रश्नपत्र लीक,नकल और परीक्षा माफिया पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा,शिवनाथ यादव ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएँ लाखों-करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ी होती हैं। ऐसे में प्रश्नपत्र लीक और संगठित परीक्षा अपराध न केवल मेहनती अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करते हैं,बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करते हैं,उन्होंने कहा कि संशोधित कानून के तहत ऐसे अपराधों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया है,जिससे परीक्षा माफिया और अनियमितताओं में शामिल लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही भी बढ़ेगी,जिससे भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी,उत्तरदायी और विश्वसनीय बनेगी,उनका कहना था कि इससे युवाओं का परीक्षा व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होगा तथा योग्य अभ्यर्थियों को उनकी मेहनत के अनुरूप निष्पक्ष अवसर प्राप्त होंगे, शिव नाथ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, कौशल विकास,रोजगार और पारदर्शी भर्ती प्रणाली को मजबूत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है,उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक युवा को उसकी योग्यता और परिश्रम के आधार पर समान अवसर मिले,उन्होंने विश्वास जताया कि लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक,2026 ईमानदार प्रतिभाओं की सुरक्षा करने, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने तथा परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में मौल का पत्थर साबित होगा।



-संवाददाता-

खड़गवा (एमसीबी),01 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

प्रदेश सरकार सुशासन,पारदर्शिता और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान का दावा करती है, इसी उद्देश्य से जिला स्तर पर नियमित कलेक्टर जनदर्शन आयोजित किए जाते हैं,ताकि आम नागरिक अपनी समस्याएँ सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकें और उनका समयबद्ध निराकरण हो सके। लेकिन मर्नेटगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के खड़गवा से सामने आए एक मामले ने जनदर्शन व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वार्ड क्रमांक 13 निवासी मुखलाल विश्वकर्मा ने 7 जुलाई 2026 को कलेक्टर जनदर्शन में लिखित आवेदन देकर पड़ोसी पर अवैध कब्जे का प्रयास, परिवार की सुरक्षा को खतरा,विवाद तथा क्षेत्र में कथित अवैध गतिविधियों की शिकायत की थी। आवेदन के साथ मोहल्ले के कई लोगों के हस्ताक्षरयुक्त समर्थन पत्र भी सौंपा गया था। लेकिन शिकायत दर्ज होने के 24 दिन बाद भी शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्हें किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी नहीं मिली है।

क्या है पूरा मामला?—शिकायतकर्ता मुखलाल विश्वकर्मा के अनुसार उनके पड़ोसी रामलाल केसरानी द्वारा उनके मकान से लगी भूमि के समीप मिट्टी डालकर कथित रूप से अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, उनका आरोप है कि लगातार मिट्टी डाले जाने से उनके



मकान की दीवार पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे दीवार गिरने की आशंका बनी हुई है,यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है, शिकायतकर्ता का कहना है कि यह केवल भूमि विवाद नहीं,बल्कि उनके परिवार की सुरक्षा का भी मामला है।

मारपीट और धमकी के भी लगाए आरोप—जनदर्शन में दिए गए आवेदन में शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया है कि इस विवाद के दौरान उनके साथ कथित रूप से धमकी,विवाद और मारपीट जैसी घटनाएँ भी हुई हैं,उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

कथित अवैध गतिविधियों की जांच की भी मांग—आवेदन में क्षेत्र में शराब एवं गांजा बेचने जैसी कथित अवैध गतिविधियों की भी उल्लेख किया गया है, शिकायतकर्ता ने इन गतिविधियों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, हालांकि इन आरोपों की अभी तक किसी सक्षम जांच एजेंसी द्वारा पुष्टि नहीं हुई है, इनकी सत्यता केवल अधिकृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

मोहल्लेवासियों ने भी दिया समर्थन—शिकायतकर्ता का दावा है कि यह केवल उनका व्यक्तिगत विवाद नहीं है, उन्होंने आवेदन के साथ मोहल्ले के कई लोगों के हस्ताक्षर भी प्रशासन को सौंपे थे,

24 दिन बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में दर्ज होकर संबंधित विभागों को भेजी गई थी, तो अब तक क्या राजस्व विभाग ने मौके का निरीक्षण किया? क्या भूमि का सीमांकन कराया गया? क्या नगर पंचायत अथवा संबंधित विभाग ने अवैध निर्माण की जांच की? क्या पुलिस ने शिकायतकर्ता की सुरक्षा को लेकर कोई कदम उठाया? क्या शिकायत पर कोई जांच रिपोर्ट तैयार हुई? यदि कार्रवाई हुई है तो उसकी जानकारी शिकायतकर्ता को क्यों नहीं दी गई?

यदि शिकायत सही है तो देरी गंभीर हो सकती है-

यदि शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए जाते हैं, तो समय पर कार्रवाई नहीं होना भविष्य में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है, वहीं यदि जांच में आरोप निराधार साबित होते हैं,तो प्रशासन को भी स्पष्ट रूप से अपनी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए,ताकि अनावश्यक विवाद समाप्त हो सके।

जिससे यह दर्शाया जा सके कि स्थानीय स्तर पर भी इस मामले को लेकर चिंता है, इसके बावजूद यदि जांच आगे नहीं बढ़ी है, तो इससे स्थानीय लोगों में भी अस्तोष दिखाई दे रहा है।

जनदर्शन की विश्वसनीयता पर भी सवाल—जनदर्शन व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की शिकायतों का शीघ्र समाधान करना है,स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि जनदर्शन में दर्ज शिकायतें भी कई सप्ताह तक लंबित रहती हैं और शिकायतकर्ता को कार्रवाई की जानकारी नहीं मिलती,तो लोगों का प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होना स्वाभाविक है।

स्थानीय लोगों की मांग—क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि पूरे मामले का

तत्काल मौके पर निरीक्षण कराया जाए, आवश्यक होने पर राजस्व विभाग से सीमांकन कराया जाए,शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए,कथित अवैध गतिविधियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर निगाह

फिलहाल यह मामला प्रशासनिक कार्रवाई की प्रतीक्षा में है, अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कलेक्टर जनदर्शन में दर्ज इस शिकायत पर संबंधित विभाग कब तक कार्रवाई करते हैं और शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच किस निष्कर्ष तक पहुंचती है।

चंदहा-बंशीपुर में तीन वर्षों से ठप पड़ा विद्युतीकरण कार्य, ग्रामीणों में भारी नाराजगी

बार-बार मांग के बावजूद नहीं जाग रहा प्रशासन, अधूरे कार्य से वनांचल के ग्रामीण परेशान

- क्या पिछली सरकार में स्वीकृत विकास कार्य राजनीति का शिकार हो रहे?
- पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मिली थी स्वीकृति, आधे से अधिक कार्य हो चुका था पूरा
- सौर ऊर्जा व्यवस्था भी बढ़ती मांग के अनुरूप नहीं दे पा रही पर्याप्त बिजली

पोल लगे, तार खिंचे, 11 केवी लाइन तैयार फिर भी नहीं पहुंची बिजली!



अंधेरे में जीने को मजबूर ग्रामीण

तीन वर्षों से अधूरा विद्युतीकरण....अंधेरे में जीने को मजबूर वनांचल के हजारों ग्रामीण

चंदहा, बंशीपुर, कचोहर, नवाटोला सहित कई गांवों में पोल, तार और 11 केवी लाइन तैयार, फिर भी नहीं जली बिजली

क्या पूर्व सरकार में स्वीकृत विकास कार्य राजनीति का शिकार हो गए? ग्रामीणों का आरोप—विभागीय उदासीनता से ठका काम, जल्द बिजली नहीं मिली तो होगा जनआंदोलन

राजन पालेख

बैकुंठपुर (कोरिया), 01 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

आजादी के 75 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के वनांचल क्षेत्र के कई गांव नियमित विद्युत सुविधा का इंतजार कर रहे हैं, विडंबना यह है कि इन गांवों तक बिजली पहुंचाने की योजना स्वीकृत हो चुकी है, करोड़ों रुपये की लागत से अधिकांश कार्य भी पूरा कर लिया गया, बिजली के खंभे खड़े हो गए, तार भी खिंच गए, 11 केवी लाइन भी तैयार कर दी गई, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं लग सके और घरों तक कनेक्शन नहीं पहुंच पाया, परिणामस्वरूप चंदहा, बंशीपुर, कचोहर, नवाटोला, कदना तथा आसपास के कई गांव आज भी अंधेरे और अधूरे विकास के बीच जीवन गुजारने को मजबूर हैं, ग्रामीणों का कहना है कि लगभग दो से तीन वर्षों से विद्युतीकरण

पहली बार मिली थी नियमित बिजली की उम्मीद

वनांचल के इन गांवों में वर्षों तक बिजली केवल सपना रही, ग्रामीणों के अनुसार पूर्व विधायक गुलाब कमरो के प्रयासों से तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान इन विद्युतविहीन गांवों के विद्युतीकरण की स्वीकृति मिली, योजना का उद्देश्य उन बस्तियों तक बिजली पहुंचाना था, जहां आज तक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड नहीं पहुंच सका था, स्वीकृति मिलने के बाद कार्य तेजी से प्रारंभ हुआ, अकलासंडी से बंशीपुर तक सैकड़ों बिजली पोल लगाए गए, 11 केवी लाइन बिछाई गई, तार खींचे गए तथा कई स्थानों पर आवश्यक तकनीकी कार्य भी पूरा कर लिया गया, ग्रामीणों को उम्मीद थी कि कुछ ही महीनों में उनके घरों में पहली बार नियमित बिजली पहुंचेगी, लेकिन यह उम्मीद अधूरी रह गई।

सरकार बदली और ठक गई विकास की रपतार?

ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव तक काम तेज गति से चलता रहा। इसके बाद लोकसभा चुनाव तक कुछ हिस्सों में काम हुआ, लेकिन फिर अचानक पूरी परियोजना ठप हो गई, इसी कारण अब ग्रामीणों के बीच यह चर्चा भी है कि क्या पिछली सरकार में स्वीकृत विकास कार्य राजनीतिक कारणों से प्रभावित हो गए हैं? हालांकि इस संबंध में बिजली विभाग या शासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

का कार्य पूरी तरह ठप्प पड़ा है, कई बार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बिजली विभाग से मांग की गई, लेकिन आश्वासन के अलावा कोई ठोस पहल नहीं हुई।

घटती-घटना की खबर के बाद कई गांवों में जली बिजली—ग्रामीण बताते हैं कि कुछ माह पूर्व दैनिक विकास के बीच जीवन गुजारने को मजबूर हैं, ग्रामीणों का कहना है कि लगभग दो से तीन वर्षों से विद्युतीकरण

अधिकारियों से चर्चा की और परिणामस्वरूप मेण्डा, लोलकी, कछड़ी, तंजरा, ठाकुरहथी, छिद्रा और भगतपुर जैसे कई गांवों में बिजली आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई, इन गांवों में भी लंबे समय तक कार्य अधूरा पड़ा था, लेकिन जनदबाव बढ़ने के बाद विभाग ने शेष कार्य पूरा कर विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी, ग्रामीणों का कहना है कि जब अन्य गांवों में बिजली पहुंच सकती है तो चंदहा और बंशीपुर के साथ भेदभाव क्यों?

सौर ऊर्जा भी अब जवाब देने लगी

वर्तमान में चंदहा, बंशीपुर और आसपास के गांव क्रेडा द्वारा संचालित सौर ऊर्जा संयंत्रों के भरोसे हैं, लेकिन यह व्यवस्था अब गांवों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है, बरसात के मौसम में लगातार बादल छाए रहने के कारण पर्याप्त धूप नहीं मिलती, इससे सोलर प्लांट पूरी क्षमता से चार्ज नहीं हो पाते और रात में कुछ घंटों बाद ही बिजली समाप्त हो जाती है, ग्रामीण बताते हैं कि पहले प्रत्येक घर में केवल दो एलईडी बल्ब जलाने की व्यवस्था थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, आज हर घर में पंखा, मोबाइल चार्जर, टेलीविजन, पानी का पंप, मिक्सर, अन्य छोटे घरेलू उपकरण का उपयोग होने लगा है, इससे संयंत्रों पर क्षमता से अधिक भार पड़ रहा है।

नई बैटरियों का भी इंतजार

ग्रामीणों के अनुसार कई गांवों में सोलर संयंत्र की बैटरियां भी अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं, क्रेडा द्वारा रखरखाव तो किया जा रहा है, लेकिन नई बैटरियों का आबंटन समय पर नहीं होने के कारण बिजली आपूर्ति और प्रभावित हो रही है।

अब कितना काम बचा है?—स्थानीय लोगों और सूत्रों के अनुसार अब बहुत अधिक कार्य शेष नहीं है, मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर स्थापित करना, घरों तक सर्विस लाइन देना, घरेलू बिजली कनेक्शन प्रदान करना, अंतिम तकनीकी परीक्षण कर विद्युत प्रवाह शुरू करना, ग्रामीणों का कहना है कि यदि विभाग गंभीरता दिखाए तो एक-दो महीने के भीतर पूरे क्षेत्र में बिजली पहुंच सकती है।

विभागीय उदासीनता पर उठ रहे सवाल—ग्रामीणों का कहना है कि यदि अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है तो केवल अंतिम चरण का कार्य वर्षों तक लंबित क्यों रखा गया? वे पूछ रहे हैं—क्या बजट समाप्त हो गया? क्या ठेकेदार ने काम छोड़ दिया? क्या विभाग ने भुगतान रोक दिया? या फिर वरिष्ठ अधिकारी उदासीनता के कारण योजना अधूरी रह गई? इन सवालों का कोई स्पष्ट उत्तर ग्रामीणों को नहीं मिल रहा।



पूर्व विधायक गुलाब कमरो

अब आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं—चंदहा, बंशीपुर, कचोहर और आसपास के गांवों के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही कार्य दोबारा प्रारंभ नहीं हुआ तो ग्रामीण चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे, उन्होंने कहा कि वर्षों तक इंतजार करने के बाद अब धैर्य जवाब देने का है।

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने उठाई आवाज—पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि उनके कार्यकाल में वनांचल के बिजलीविहीन गांवों की समस्या को गंभीरता से उठाया गया था, उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री से मांग कर इन गांवों के विद्युतीकरण की स्वीकृति दिलाई थी, जिसके बाद तेजी से कार्य प्रारंभ हुआ, उन्होंने आरोप लगाया कि

सरकार बदलने के बाद अधिकांश विकास कार्यों की गति रुक गई, उन्होंने कहा कि चंदहा, नवाटोला, कचोहर, तंजरा, ठाकुरहथी और बंशीपुर सहित कई गांवों में कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, यदि विभाग शीघ्र कार्य पूरा नहीं करता तो ग्रामीणों के साथ मिलकर व्यापक आंदोलन किया जाएगा।

ग्रामीणों का अंतिम सवाल हमारे गांव में बिजली कब?

वनांचल के ग्रामीण कहते हैं कि जब आसपास के गांवों में बिजली पहुंच चुकी है और उनके गांवों में भी अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है, तब उन्हें और कितने वर्षों तक इंतजार करना होगा? ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की सुस्ती और प्रशासनिक उदासीनता के कारण हजारों लोग आज भी आधुनिक जीवन की सबसे बुनियादी सुविधा—बिजली—से वंचित हैं, अब पूरा क्षेत्र इस इंतजार में है कि विभाग कब अधूरा काम पूरा करेगा और वर्षों से अंधेरे में डूबे चंदहा, बंशीपुर, कचोहर, नवाटोला और आसपास के गांवों में आखिर कब स्थायी रूप से बिजली का उजाला पहुंचेगा।

‘बैगलेस डे’ पर स्कूल बने देशभक्ति और प्रेरणा के केंद्र

महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों की चित्र प्रदर्शनी ने बच्चों में जगाया राष्ट्रभक्ति का भाव

शहीद परिजन, भूतपूर्व सैनिक, समाजसेवी और विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों से किया संवाद, पेंटिंग प्रतियोगिता और न्योता भोजन भी बना आकर्षण

—संवाददाता—

सूरजपुर, 01 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित न रहे, बल्कि विद्यार्थियों में रचनात्मकता, राष्ट्रभक्ति, सामाजिक सरोकार और नैतिक मूल्यों का भी विकास हो—इसी उद्देश्य के साथ जिले के सभी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शनिवार को ‘बैगलेस डे’ उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालयों में महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर शहीदों और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली विभूतियों के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी, पेंटिंग प्रतियोगिता, प्रेक्षक व्याख्यान, संवाद कार्यक्रम तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया, कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर श्रीमती रेना जमील एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन, जिला शिक्षा अधिकारी लता बेक तथा जिला मिशन समन्वयक मनोज कुमार साहू के निर्देशन में जिले के सभी शासकीय विद्यालयों में एक साथ किया गया।

कितानों की जगह रंगों से सीखा इतिहास—बैगलेस डे के तहत इस बार विद्यार्थियों ने पुस्तकों के बजाय रंगों और

प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र

विद्यालयों में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का शिक्षकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने भी अवलोकन किया, प्रदर्शनी के माध्यम से विद्यार्थियों को महापुरुषों के जीवन, उनके संघर्ष, त्याग और राष्ट्र निर्माण में योगदान की जानकारी दी गई, बच्चों ने स्वयं अपने चित्रों का परिचय देते हुए बताया कि वे किस महापुरुष से प्रेरणा लेते हैं और क्यों।

शहीद परिवारों ने सुनाई बलिदान की गाथा

प्रतापपुर विकासखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू परमानंद कोसरिया के पुत्र कमलेश कोसरिया तथा सीमा पर देश सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक शिवचरण नापित विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, उन्होंने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता आंदोलन, देशभक्ति और राष्ट्रसेवा के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी, इसी प्रकार सूरजपुर विकासखंड के माध्यमिक शाला रुनियाडीह में शहीद परिवार के प्रतिनिधि अंकित कोसरिया ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की प्रेरक कहानियां साझा कीं।

कल्पनाशीलता के माध्यम से इतिहास को समझने का प्रयास किया, बच्चों ने स्वयं महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, डॉ. भीमराव अंबेडकर, बिरसा मुंडा, स्वामी विवेकानंद, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सहित अनेक महापुरुषों और अमर शहीदों के चित्र बनाए, स्क्रीच आर्ट, रंगोली शैली, पेंटिंग एवं हस्तनिर्मित पोस्टरों के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी कला का परिचय देते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विद्यालय परिसर देशभक्ति के रंगों से सराबोर दिखाई दिए।

स्वतंत्रता सेनानी गोकुल प्रसाद के संघर्ष का किया स्मरण कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्वतंत्रता—संग्राम सेनानी गोकुल प्रसाद के जीवन पर भी प्रकाश

झला, बताया गया कि वर्ष 1925 में वे दुर्ग से उदयपुर पहुंचे और बाद में सूरजपुर क्षेत्र आए, हरिद्वार में आर्य समाज के संपर्क में आने के बाद वे वंदे मातरम आंदोलन से जुड़े, हैदराबाद में आयोजित आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जहां अमानवीय यातनाएं सहते हुए 1 अप्रैल 1939 को उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वक्ताओं ने कहा कि ऐसे महान बलिदानों की जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है।

विशेषज्ञों ने साझा किए सफलता के अनुभव—भैयाथान विकासखंड के हयर सेकेंडरी स्कूल गंगोटी में अधिवक्ता अनिल गोयल, पूर्व एसडीओ जल संसाधन एस.के. तिवारी, सेवानिवृत्त शिक्षक रविशंकर मिश्रा,

समाजसेवी लालचंद अग्रवाल तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन, परिश्रम और नैतिकता का महत्व बताया, वहीं रामानुजगंजर विकासखंड के बालक माध्यमिक शाला रामानुजगंजर में अस्थिर रोग विशेषज्ञ डॉ. अजय साहू, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वयं गोयल तथा जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा ने विद्यार्थियों से संवाद किया, उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और सफलता की कहानियां साझा करते हुए बच्चों को बड़े सपने देखने और उन्हें मेहनत से पूरा करने की प्रेरणा दी, विद्यार्थियों ने भी अपने भविष्य के लक्ष्य बताते हुए डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक, शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी बनने की इच्छा व्यक्त की।

प्रतियोगिताओं में दिखाई रचनात्मकता—बैगलेस डे के दौरान विभिन्न विद्यालयों में चित्रकला एवं पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया, इससे बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिला।

पोषण वाटिका और न्योता भोजन भी बना आकर्षण—शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ विद्यालयों में पोषण वाटिका का विस्तार भी किया गया, इसके अलावा न्योता भोजन कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की गई, इससे विद्यालय और समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया।

“बैगलेस डे” के अवसर पर स्कूलों में महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित

छात्रों ने पेंटिंग व चित्रकारी के माध्यम से अमर शहीदों की श्रद्धांजलि, शहीद परिजन एवं भूतपूर्व सैनिक हूट शामिल



● कलेक्टर रेना जमील और CEO विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन में शिक्षकों के विद्यालयों में आयोजन ● शहीद परिजन, भूतपूर्व सैनिक, समाजसेवी और विशेषज्ञों ने बच्चों को दिए प्रेरक संदेश ● चित्रकला प्रतियोगिता में अवसर छात्रों को किया गया गुरुकुल ● पोषण वाटिका का विस्तार और न्योता भोजन भी हुआ अखंड

हर शनिवार होगा सीखने का नया अनुभव

जिला मिशन समन्वयक मनोज कुमार साहू ने बताया कि ‘बैगलेस डे’ स्कूल शिक्षा विभाग एवं राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा की पहल है, यह प्रत्येक शनिवार आयोजित होने वाला सतत कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य बच्चों को पारंपरिक पढ़ाई के साथ-साथ व्यवहारिक, रचनात्मक एवं अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करना है, उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जनप्रतिनिधियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों—कर्मचारियों, समाजसेवियों, सफल व्यक्तियों, पालकों एवं स्कूल प्रबंधन समितियों को विद्यालयों से जोड़कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का प्रयास किया जा रहा है।

शिक्षा के साथ संतकालों का भी हुआ समावेश

कार्यक्रम में सहायक संचालक शिक्षा अजय सिंह, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्वीत समन्वयक, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य एवं संकुल समन्वयकों सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर गतिविधियों का अवलोकन किया, बैगलेस डे के इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि शिक्षा केवल परीक्षा और अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों में देशभक्ति, संस्कार, सामाजिक उत्तरदायित्व, रचनात्मकता और व्यक्तित्व विकास के अवसर भी समाान रूप से महत्वपूर्ण हैं, महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से प्रेरणा लेकर विद्यार्थी न केवल अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।



भाग-1

जहां डॉक्टर नहीं पहुंचते थे, वहां स्वास्थ्य की दस्तक

मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान बना स्वास्थ्य विभाग की ऐतिहासिक उपलब्धि

- 13 अप्रैल से अभियान की शुरुआत
- 1300 स्वास्थ्य टीमों ने किया काम
- 34.29 लाख लोगों की हुई जांच
- 6 हजार से ज्यादा गंभीर मरीज मिले
- 10,938 हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान
- दूसरा चरण 31 अगस्त तक जारी



नक्सल प्रभावित बस्तर में घर-घर पहुंची स्वास्थ्य टीम, हर व्यक्ति की जांच, हर मरीज तक इलाज

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा-नक्सल प्रभावित बस्तर में घर-घर पहुंची स्वास्थ्य टीम, हजारों गंभीर मरीजों और हाई रिस्क गर्भवतियों की पहचान

46 मिनट की प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गिनाई उपलब्धियां, कहा—स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य

विशेष श्रृंखला भाग-1

ढाई साल का स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड: 'स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं'

यूज डेस्क

रायपुर, 01 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने लगभग ढाई वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा राजधानी रायपुर में आयोजित लगभग 46 मिनट की प्रेस वार्ता में रखा, प्रेस वार्ता में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए कार्यों, नई योजनाओं, अधोसंरचना के विस्तार, भर्ती, चिकित्सा शिक्षा, खाद्य सुरक्षा तथा बस्तर सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को लेकर आंकड़ों सहित जानकारी दी, प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, स्वास्थ्य आयुक्त संजिव झा, आयुष विभाग के संचालक डॉ. राजेंद्र कटारा, सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक उज्ज्वल पुरवार सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

मीडिया का जताया आभार-अपने संबोधन की शुरुआत में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मीडिया जनता और सरकार के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, उन्होंने कहा कि कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां

स्वस्थ बस्तर अभियान मेरे जीवन का सबसे भावनात्मक अभियान

प्रेस वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्री कई बार भावुक भी नजर आए... उन्होंने कहा कि जब भी मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान की चर्चा होती है तो उनके मन में विशेष भावनाएं उमड़ पड़ती हैं, उन्होंने कहा—ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में मैंने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा कि मुझे स्वास्थ्य जैसा विभाग मिला और वह भी छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां बस्तर जैसा विशाल और वर्षों तक नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्र है, उन्होंने कहा कि बस्तर में ऐसे अनेक गांव हैं जहां दशकों तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच सकीं, कई गांव ऐसे रहे जहां लोगों ने न कभी डॉक्टर देखा, न नर्स और न ही आधुनिक दवाइयों की सुविधा प्राप्त की।

नक्सलवाद के कारण वर्षों तक स्वास्थ्य सेवाओं से दूर रहे गांव

मंत्री ने बताया कि नक्सलवाद के कारण अनेक गांव सड़क, बिजली और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गए, उन्होंने कहा कि कई गांवों तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, अनेक क्षेत्रों में सड़क तक नहीं थी, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वहां पहुंचना जोखिम भरा था, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता था, ऐसी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान शुरू किया गया।

प्रशासनिक अधिकारी भी नियमित रूप से नहीं पहुंच पाते, लेकिन मीडिया वहां तक पहुंचकर वास्तविक स्थिति सामने लाता है, उन्होंने सभी मीडिया संस्थानों का स्वागत करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यों को जनता तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

13 अप्रैल से शुरू हुआ अभियान-मंत्री ने बताया कि इस अभियान का शुभारंभ 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में किया गया, अभियान की शुरुआत एक साथ लगभग 1100 स्थानों से की गई, इस पूरे अभियान में लगभग 1300 स्वास्थ्य टीमों को लगाया गया, इन टीमों में शामिल थे—चिकित्सक, स्टाफ नर्स,

पैरामेडिकल स्टाफ, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन।

34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच-मंत्री ने बताया कि अभियान का लक्ष्य लगभग 36 लाख आबादी तक पहुंचना था, हालांकि इनमें से कुछ लोग बाहर रोजगार के लिए चले गए थे तथा कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण वास्तविक लक्ष्य में अंतर आया, इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 34 लाख 29 हजार लोगों की स्क्रीनिंग कर लक्ष्य का लगभग शत-प्रतिशत हासिल कर लिया, उन्होंने कहा कि यह केवल सरकारी उपलब्धि नहीं बल्कि पूरे बस्तर क्षेत्र की जनता की सफलता है।

मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान से लेकर अस्पतालों के विस्तार, डॉक्टरों की भर्ती मातृ-शिशु सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा तक विभागीय कार्यों का रखा विस्तृत ब्यौरा

घर-घर पहुंची स्वास्थ्य टीम

मंत्री ने बताया कि अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमों गांव-गांव और घर-घर पहुंचीं, प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की गई, जांच में शामिल थे रक्तचाप (बीपी), ब्लड शुगर, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, बुखार की जांच, आवश्यक दवाइयों का वितरण जहां मामूली बीमारी मिली, वहीं उपचार उपलब्ध कराया गया।

गंभीर मरीजों के लिए बनाया रेफरल सिस्टम

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभियान केवल जांच तक सीमित नहीं रहा, यदि किसी मरीज की स्थिति गंभीर पाई गई तो उसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आवश्यकता पड़ने पर जिला अस्पताल, और जरूरत होने पर रायपुर के बड़े अस्पतालों तक भेजा गया, उन्होंने कहा कि पहली बार बस्तर के दूरस्थ गांवों के लोगों को व्यवस्थित रेफरल प्रणाली का लाभ मिला।

6000 से अधिक गंभीर मरीजों को उच्च चिकित्सा संस्थानों में भेजा गया...

मंत्री ने बताया कि अभियान के दौरान लगभग 6000 ऐसे मरीज मिले जिन्हें उच्च स्तरीय चिकित्सा की आवश्यकता थी, इन सभी मरीजों को चरणबद्ध तरीके से विशेषज्ञ अस्पतालों में भेजा गया, कुछ मरीजों का उपचार अभी भी जारी है।

10,938 हाई रिस्क गर्भवतियों की पहचान- प्रेस वार्ता का एक महत्वपूर्ण बिंदु मातृ स्वास्थ्य रहा, मंत्री ने बताया कि अभियान के दौरान 10,938 हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं की पहचान की गई, ऐसी महिलाओं की नियमित निगरानी शुरू की गई, विशेषज्ञ चिकित्सकों से जांच कराई गई, सुरक्षित संस्थागत प्रसव की व्यवस्था की गई, उन्होंने कहा कि मातृ मृत्यु दर कम करने में यह अभियान महत्वपूर्ण साबित होगा।

अभियान का दूसरा चरण शुरू-मंत्री ने बताया कि पहले चरण में केवल पहचान

और स्क्रीनिंग का कार्य किया गया, अब दूसरा चरण चल रहा है, इसमें चिन्हित मरीजों का उपचार, विशेषज्ञ परामर्श, रेफरल, फॉलोअप किया जा रहा है, यह चरण 31 अगस्त तक चलेगा।

स्वास्थ्य कर्मियों को दिया श्रेय-मंत्री ने विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों की सराहना की, उन्होंने कहा कि यदि मितानिन, नर्स, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव और स्थानीय जनप्रतिनिधि सहयोग नहीं करते तो इतना बड़ा अभियान सफल नहीं हो सकता था, उन्होंने अभियान

से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।

बस्तर में स्वास्थ्य सेवा का नया अध्याय

मंत्री ने कहा कि वर्षों तक नक्सल प्रभावित रहा बस्तर अब विकास और स्वास्थ्य सेवाओं के नए दौर में प्रवेश कर रहा है, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य केवल इलाज करना नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति तक समय पर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है, उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में बस्तर में और अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक उपकरण और नई स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

अगले भाग (भाग-2) में पढ़िए...

- ढाई वर्षों में स्वास्थ्य अधोसंरचना का विस्तार
- 11 उप स्वास्थ्य केंद्र, 43 पीएचसी, नए अस्पतालों की स्थापना
- 1000 नए डॉक्टरों की भर्ती
- 3000 से अधिक नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ
- मातृ मृत्यु दर में सुधार
- 450 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
- मलेरिया नियंत्रण की रणनीति
- टीबी मुक्त पंचायतों की सफलता
- और कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं।

युवा ज्ञान, नवाचार और नैतिक मूल्यों से करें राष्ट्र निर्माण : राज्यपाल रमेन डेका

रायपुर, 01 अगस्त 2026। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि ज्ञान को विवेक, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जनकल्याण के लिए उपयोग में लाना है। एक शिक्षित व्यक्ति की पहचान उसके प्रमाण-पत्रों से नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उसके योगदान से होती है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने जीवन में कम से कम एक ऐसा कार्य अवश्य करें, जो समाज के लिए स्थायी रूप से लाभकारी सिद्ध हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। राज्यपाल डेका रायगढ़ स्थित ओ.पी. जिनंदल विश्वविद्यालय के छठवें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। समारोह में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट तथा स्कूल ऑफ साइंस के 688 विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान की गईं। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले 27 विद्यार्थियों को स्वर्ण, 28 को रजत तथा 29 विद्यार्थियों को कांस्य पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया।

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि वर्तमान समय तेजी से बदलती तकनीक, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का दौर है। ऐसे समय में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका केवल शिक्षण तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उन्हें ऐसे युवा तैयार करने होंगे जो ज्ञान के साथ संवेदनशीलता, नेतृत्व क्षमता, अनुसंधान की प्रवृत्ति और सामाजिक सरोकारों को भी अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा की सच्ची सार्थकता केवल उपाधि प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उस ज्ञान को समझदारी, दूरदर्शिता और नैतिक साहस के साथ जीवन में उतारने में है। आपका ज्ञान तभी पूर्ण होगा, जब वह समाज और मानवता के कल्याण में उपयोगी बने। जीवन में कम से कम एक ऐसा कार्य अवश्य करें, जो समाज के लिए स्थायी रूप से लाभकारी सिद्ध हो। विश्वास व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर निकलने वाले युवा अपने ज्ञान, प्रतिभा और संस्कारों के बल पर देश के विकास तथा समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।



चार दिन तक मिट्टी के नीचे दबी रही जिंदगी.... पाइपलाइन कार्य में लापरवाही ने ली मजदूर की जान

कांकेर, 01 अगस्त 2026। जिले के भानुप्रतापुर थाना क्षेत्र में जल जीवन मिशन (नल-जल योजना) के कार्य के दौरान हुई कथित लापरवाही ने एक मजदूर की जान ले ली। पाइपलाइन का घरेलू कनेक्शन जोड़ने के लिए गड्डे में उतरा मजदूर जेसीबी से खलौ गई मिट्टी में जंदा दब गया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। हेरानी की बात यह रही कि चार दिन बाद उसी स्थान की दोबारा खुदाई में उसका शव बैठी हुई अवस्था में बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार ग्राम हिंगानझर में नल-जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। 28 जुलाई को 30 वर्षीय रामदेव आंचला पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्डे में उतरकर घरेलू कनेक्शन जोड़ रहा था। इसी दौरान दूसरी ओर से गड्डा भर रहा जेसीबी चालक अनजाने में



उसी हिस्से पर भी मिट्टी डालता चला गया, जहां रामदेव काम कर रहा था। मिट्टी इतनी तेजी से भर गई कि मजदूर को बाहर निकलने या मदद के लिए आवाज लगाने का भी मौका नहीं मिला। घटना के समय अन्य मजदूर 20 से 40 मीटर दूर काम कर रहे थे, जिससे किसी को हदसे का एहसास तक नहीं हुआ। दोपहर के भोजन के समय जब रामदेव नहीं पहुंचा तो साथियों ने

उसकी तलाश शुरू की। शुरुआत में मोबाइल पर घंटी जाती रही, लेकिन कुछ समय बाद फोन भी बंद हो गया। परिजनों और ग्रामीणों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद कच्चे चौकी में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। 31 जुलाई को पुलिस, ग्रामीणों और सरपंच की मौजूदगी में उस स्थान पर दोबारा खुदाई कराई गई, जहां रामदेव आखिरी बार काम करते देखा गया था। करीब 10 मीटर तक खुदाई करने के बाद गड्डे के भीतर बैठी हुई अवस्था में उसका शव बरामद हुआ। यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग भी स्तब्ध रह गए। मजदूर का शव बाहर निकलते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जेसीबी चालक के साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर चालक को हिरासत में लिया।

सीएम साय ने आतंकी हमले में मारे गए भूपेंद्र और दीपक के परिवार को 20-20 लाख देने की घोषणा की

रायपुर, 01 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुलगाम (जम्मू-कश्मीर) आतंकी हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ के दो श्रमिकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने घटना की निंदा करते हुए मृतात्माओं की शांति की प्रार्थना की। दिल्ली के दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने

बताया कि बस्तर पंडुम के विजेताओं का राष्ट्रपति ने सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नक्सल मुक्त बस्तर में जो गतिविधि चल रही है उसकी जानकारी दी, वहां विद्युतीकरण की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूर करने का आयोगन किया, आयुर्वेद का एम्स खोलने की भी मांग प्रधानमंत्री से की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि विकास के काम तेजी से होंगे। आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री की

मौजूदगी में लखपति दीदी को लेकर सम्मेलन होगा। वहीं महानदी जल विवाद को लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री के साथ जल शक्ति मंत्री के साथ हुई बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों प्रदेश के हित को देखते हुए निर्णय होगा, आने वाले तीन महीने में जल बंटवारे का निर्णय हो जाने की उम्मीद है। इसके साथ उन्होंने कहा कि कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन मिलने वाला है। रेल मंत्री से

मुलाकात में इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कुछ और रेल लाइन की स्वीकृति को लेकर भी बातचीत हुई है। बस्तर में भी किरेंदुल से बीजापुर जैसी जगहों के लिए रेल लाइन पर चर्चा हुई है। सीएम साय ने बताया कि नये मोबाइल टावर के लिए भी केंद्रीय मंत्री से बात हुई है, नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में पहले जो 500 से ज्यादा मोबाइल टावर मिले उसके लिए धन्यवाद दिया।

दो जिला अध्यक्षों की बहस से बड़ी सियासी हलचल, कांग्रेस का हमला

भिलाई, 01 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो पदाधिकारियों के बीच हुई कथित फोन बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह बातचीत भिलाई भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष खगेश कोसरिया के बीच हुई थी। कथित बातचीत में पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के लिए नाश्ते और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा सुनाई दे रही है। हालांकि, वायरल ऑडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर हुई कथित बातचीत

सोशल मीडिया पर वायरल कथित ऑडियो के अनुसार, पार्टी के कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों के स्वागत और नाश्ते की व्यवस्था को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। बातचीत में बेहतर आतिथ्य व्यवस्था, नाश्ता, पानी और अन्य आवश्यक इंतजामों पर चर्चा की गई। कथित तौर पर जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने कहा कि बाहर से आने वाले अतिथियों के सामने संगठन की अच्छी छवि प्रस्तुत करना जरूरी है और कार्यक्रम की व्यवस्था उसी स्तर की होनी चाहिए।

आर्थिक स्थिति का हवाला देने का दावा

कथित ऑडियो में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष खगेश कोसरिया अपनी आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए अतिरिक्त खर्च उठाने में असमर्थता जताते हुए सुनाई देते हैं। बातचीत के अनुसार उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से उनका कारोबार ठीक नहीं चल रहा है और वे अपनी क्षमता से अधिक खर्च नहीं कर सकते। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यक्रम के लिए सामान्य स्तर पर चाय, समोसा, जलेबी और पानी जैसी बुनियादी व्यवस्था पर्याप्त रहेगी, ताकि कार्यक्रम भी हो जाए और अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी न पड़े।